केवाईसी पर मास्टर निदेश में संशोधन पर परिपत्र का अनुबंध

अनुबंध

I. लाभार्थी स्वामी की पहचान

क) लाभार्थी स्वामी (बीओ) के निर्धारण के उद्देश्य से "स्वामित्व हित को नियंत्रित करने" की सीमा को कंपनियों और न्यास दोनों के लिए क्रमशः 25 प्रतिशत और 15 प्रतिशत की पूर्व सीमा से संशोधित कर 10 प्रतिशत कर दिया गया है।

ख) बीओ की पहचान से छूट: बीओ की पहचान से छूट को पीएमएल नियम, 2005 में प्रदान किए गए विवरण के साथ संरेखित किया गया है, उदाहरण के लिए जहां ग्राहक या नियंत्रक हित का स्वामी (i) भारत में स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध एक इकाई है या (ii) केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्राधिकार में रहने वाली एक इकाई है और ऐसे अधिकार क्षेत्रों में स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध है, या (iii) ऐसी सूचीबद्ध इकाइयों की सहायक इकाई है; ऐसी इकाई के किसी शेयरधारक या लाभकारी स्वामी की पहचान करना और पहचान की पुष्टि करना आवश्यक नहीं है।

II. गैर-वैयक्तिक ग्राहकों की कुछ श्रेणियों के मामले में सीडीडी उपाय

गैर-वैयक्तिक ग्राहकों की निम्नलिखित श्रेणियों से संबंधित सीडीडी उपायों में कुछ अतिरिक्त जानकारी/दस्तावेज़ आवश्यकताओं को शामिल करने के लिए संशोधन किया गया है:

क) कंपनियां -

(i) वरिष्ठ प्रबंधन पद धारण करने वाले उपयुक्त व्यक्तियों के नाम; और

(ii) पंजीकृत कार्यालय और उसके व्यवसाय का प्रमुख स्थान, यदि वह भिन्न है।

ख) भागीदार फर्म -

(i) सभी भागीदारों के नाम; और

(ii) पंजीकृत कार्यालय का पता और उसके व्यवसाय का प्रमुख स्थान, यदि वह अलग है।

ग) न्यास -

(i) न्यास के लाभार्थियों, न्यासियों, सेटलर और लेखकों के नाम

(ii) न्यास के पंजीकृत कार्यालय का पता; और

(iii) न्यासियों और दस्तावेजों की सूची, जैसा धारा 16 में निर्दिष्ट है, उनके लिए जो न्यासी के रूप में भूमिका निभा रहे हैं और न्यास की ओर से लेन-देन करने के लिए अधिकृत हैं।

इसके अलावा, धारा 33बी को एक ऐसे ग्राहक के लिए लागू करने के लिए संशोधित किया गया है जो न्यायिक व्यक्ति या व्यक्ति या न्यास की ओर से कार्य करने का दावा करता है।

(यह ध्यान दिया जाए कि पुराने खातों के संदर्भ में उपरोक्त पैरा ।(क) और ।। में दिए गए अनुदेशों का अनुपालन आरई द्वारा समयबद्ध तरीके से किया जाएगा)

III. अभिलेख प्रबंधन

क) 'अभिलेख प्रबंधन' पर अनुदेशों में स्पष्टीकरण प्रदान किया गया है जैसे वाक्यांश "पहचान से संबंधित अभिलेख", "पहचान अभिलेख", आदि में पहचान डेटा, खाता फाइलों, व्यापार पत्राचार के अद्यतन अभिलेख और किए गए किसी भी विश्लेषण के परिणाम शामिल होंगे।

ख) आरई को सूचित करते हुए अनुदेश शामिल किए गए हैं ताकि ऐसे ग्राहकों के मामले में जो गैर-लाभकारी संगठन हैं, उन ग्राहकों का विवरण नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत किया जाना सुनिश्चित किया जा सके। यदि ऐसे ग्राहक पंजीकृत नहीं हैं, तो आरई दर्पण पोर्टल पर विवरण दर्ज करेगा। आरई ग्राहक और आरई के बीच कारोबार संबंध समाप्त होने या खाता बंद होने के बाद, जो भी बाद में हो, पांच साल की अवधि के लिए ऐसे पंजीकरण अभिलेख बनाए रखेंगे।

IV. केवाईसी का अद्यतन/आवधिक अद्यतन

क) आधार ओटीपी आधारित ई-केवाईसी के अप्रत्यक्ष रूप को आवधिक अद्यतनीकरण के लिए उपयोग करने की अनुमति दी गई है। यदि वर्तमान पता आधार में दिए गए पते से भिन्न है, तो इस मामले में वर्तमान पते की घोषणा की सकारात्मक पुष्टि की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, किसी भी धोखाधड़ी को रोकने के लिए, आरई को यह सुनिश्चित करना होगा कि आधार प्रमाणीकरण के लिए मोबाइल नंबर वही है जो ग्राहक की दर्ज सूचना में उनके पास उपलब्ध है।

ख) धारा 38 के 'अतिरिक्त उपायों' पर उप-धारा (ग) के खंड (vi) को हटा दिया गया है।

ग) पीएमएल नियमों की आवश्यकताओं के संदर्भ में ग्राहकों के दायित्व पर अनुदेश शामिल किए गए हैं– आरई ग्राहकों को सूचित करेंगे कि पीएमएल नियमों का पालन करने के क्रम में, कारोबार संबंध/खाता-आधारित संबंध स्थापित करते समय और आवश्यकतानुसार बाद में ग्राहक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में किसी भी अद्यतन के मामले में, ग्राहकों को ऐसे दस्तावेज़ों का अद्यतन विवरण आरई को

प्रस्तुत करना होगा। यह आरई के अभिलेख को अद्यतन करने के उद्देश्य से दस्तावेजों को अद्यतन करने के 30 दिनों के भीतर किया जाएगा।

V. अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के संचार के तहत आवश्यकताएँ / दायित्व

क) धारा 51 को यह निर्धारित करने के लिए संशोधित किया गया है कि यूएनएससी प्रतिबंध सूची और आतंकवाद की रोकथाम और दमन (सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का कार्यान्वयन) आदेश, 2007 की अनुसूचियों में उपलब्ध सूचियों को दैनिक आधार पर सत्यापित किया जाएगा और किसी भी संशोधन के लिए जोड़ने, हटाने या अन्य परिवर्तनों के संदर्भ में सूचियों को आरई द्वारा सावधानीपूर्वक अनुपालन के लिए ध्यान में रखा जाएगा।

अध्याय IX में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) से संबंधित मौजूदा प्रावधानों को मास्टर निदेश की धारा 51 में समेकित किया गया है।

ख) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 30 जनवरी 2023 को "सामूहिक विनाश के हथियार (डब्ल्यूएमडी) और उनको उपलब्ध कराने की प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005 (डब्ल्यूएमडी अधिनियम, 2005) की धारा 12ए के कार्यान्वयन की प्रक्रिया" पर जारी आदेश के अनुपालन के संबंध में आरई द्वारा सावधानीपूर्वक अनुपालन के लिए अनुदेशों को धारा 52 में जोड़ा गया है। आदेश डबल्यूएमडी अधिनियम, 2005 की धारा 12ए के तहत दी गई सूची के तहत निर्दिष्ट व्यक्तियों/ संस्थाओं के खातों, वित्तीय संपत्तियों आदि को इस्तेमाल हेतु रोकने / मुक्त करने के लिए हितधारकों द्वारा की जाने वाली विस्तृत आवश्यकताओं और कार्रवाई को निर्धारित करता है।

उपर्युक्त आदेश के तहत आरई पर डाले गए कुछ महत्वपूर्ण दायित्वों का सारांश नीचे दिया गया है:

(i) पूर्वोक्त आदेश के पैरा 3 के अनुसार, आरई यह सुनिश्चित करेंगे कि निर्दिष्ट सूची में दिए गए विवरण के साथ व्यक्ति / संस्था के विवरण के मिलान के मामले में लेनदेन नहीं किया जाएगा।

(ii) इसके अलावा, आरई ग्राहक के साथ संबंध स्थापित करते समय और आवधिक आधार पर यह सत्यापित करने के लिए कि निर्दिष्ट सूची में व्यक्तियों और संस्थाओं के पास बैंक खाते आदि के रूप में कोई निधि, वित्तीय संपत्ति आदि है या नहीं, दिए गए मापदंडों पर जांच करेंगे।

(iii) उपरोक्त मामलों में मिलान के मामले में, आरई तुरंत केंद्रीय नोडल अधिकारी (सीएनओ) को शामिल निधि, वित्तीय संपत्ति या आर्थिक संसाधनों के पूरे विवरण के साथ लेनदेन विवरण की सूचना देगा, जिसे डबल्यूएमडी अधिनियम, 2005 की धारा 12ए के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकरण के

रूप में नामित किया गया है। सूचना की एक प्रति राज्य नोडल अधिकारी, जहां खाता / लेनदेन होता है और आरबीआई को भेजी जाएगी। एफआईयू-आईएनडी के साथ आरई एक एसटीआर फाइल करेंगे, जिसमें ऊपर वर्णन किए गए, खातों में किए गए या प्रयास किए गए सभी लेनदेन शामिल होंगे।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि आदेश के पैरा 1 के अनुसार, निदेशक, एफ़आईयू इंडिया को सीएनओ के रूप में नामित किया गया है।

(iv) आरई एफआईयू-इंडिया के पोर्टल पर उपलब्ध समय-समय पर संशोधित नामित सूची का संदर्भ ले सकते हैं।

(v) यदि संदेह से परे विश्वास करने के कारण हैं, कि ग्राहक द्वारा धारित धन या संपत्ति डब्ल्यूएमडी अधिनियम, 2005 की धारा 12ए की उप-धारा (2) के खंड (ए) या (बी) के दायरे में आएगी, आरई बिना किसी देरी के सीएनओ को ईमेल, फैक्स और डाक द्वारा सूचित करते हुए ऐसे व्यक्ति/संस्था को वित्तीय लेनदेन करने से रोकेंगे।

(vi) यदि सीएनओ से आरई द्वारा धारा 12ए के तहत संपत्ति को इस्तेमाल हेतु रोकने का आदेश प्राप्त होता है, तो आरई बिना किसी देरी के आदेश का पालन करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

(vii) आदेश के पैरा 7 के अनुसार निधियों आदि को मुक्त करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तदनुसार, किसी व्यक्ति/संस्था से संपत्ति को मुक्त करने के संबंध में प्राप्त आवेदन की प्रति को आरई द्वारा सीएनओ को ईमेल, फैक्स और डाक द्वारा, दो कार्य दिवसों के भीतर जमा की गई संपत्ति के पूर्ण विवरण के साथ, जैसा कि आवेदक द्वारा दिया गया है, अग्रेषित किया जाएगा।

ग) इसके अलावा, धारा 52 में मौजूदा अनुदेश अर्थात, "उपर्युक्त के अलावा, समय-समय पर किसी अन्य अधिकार क्षेत्र / संस्थाओं के संबंध में रिजर्व बैंक द्वारा परिचालित अन्य यूएनएससीआर पर भी ध्यान दिया जाएगा", संशोधित किया गया है और धारा 53ए के रूप में जोड़ा गया है जो निम्नानुसार है:

"उपर्युक्त के अलावा, आरई को ध्यान में रखना होगा - (ए) अन्य यूएनएससीआर और (बी) यूएपीए, 1967 की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में सूचियां और यूएपीए की धारा 51ए और डब्ल्यूएमडी अधिनियम की धारा 12ए के कार्यान्वयन पर सरकारी आदेशों के अनुपालन के लिए इसमें कोई भी संशोधन''।

घ) धारा 52 के माध्यम से, आरई को अनिवार्य किया गया है कि वे हर दिन, ' नामित व्यक्तियों और संस्थाओं की यूएनएससीआर 1718 प्रतिबंध सूची' को सत्यापित करेंगे, जो

https://www.mea.gov.in/Implementation-of-UNSC-Sanctions-DPRK.htm पर उपलब्ध है, ताकि केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित अनुसार जोड़ने, हटाने या अन्य परिवर्तनों के माध्यम से सूची में किसी भी संशोधन को ध्यान में रखने के लिए और 'लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य कोरिया आदेश, 2017 पर सुरक्षा परिषद के संकल्प के कार्यान्वयन' के रूप में संशोधित अनुपालन को भी सुनिश्चित किया जा सके।

VI. शेल बैंक

'शेल बैंक' की परिभाषा में संशोधन कर इसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा -

"शेल बैंक का मतलब वह बैंक है जिसकी देश में कोई भौतिक उपस्थिति नहीं है जिसमें कि इसे शामिल किया गया है और लाइसेंस दिया गया है, और जो एक विनियमित वित्तीय समूह से असंबद्ध है जो प्रभावी समेकित पर्यवेक्षण के अधीन है। भौतिक उपस्थिति का अर्थ है, एक देश के भीतर स्थित सार्थक निर्णय और प्रबंधन। केवल एक स्थानीय एजेंट या नीचे के स्तर के कर्मचारियों का अस्तित्व भौतिक उपस्थिति नहीं माना जाएगा"।

VII. प्रतिनिधि बैंकिंग

प्रतिनिधि बैंकिंग संबंधों के संबंध में निर्देश अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं। बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि नए प्रतिनिधि बैंकिंग संबंध स्थापित करने के लिए वरिष्ठ प्रबंधन का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाए। बैंक सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी का उपयोग करेंगे, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, (ए) प्रतिवादी संस्थान की प्रतिष्ठा से संबंधित जानकारी (बी) संबंधित क्षेत्राधिकार में पर्यवेक्षण की गुणवत्ता (सी) क्या प्रतिवादी संस्थान किसी भी जांच या धन शोधन /आतंकवादी वित्तपोषण से संबंधित विनियामक कार्रवाई के अधीन है।

इसके अलावा, 'प्रतिनिधि बैंकिंग' और 'पेएबल-थ्रू अकाउंट्स' की परिभाषाएं जोड़ी गई हैं।

VIII. ग्राहक स्वीकृति नीति

जहां आरई को धन शोधन या आतंकवादी गतिविधि के वित्तपोषण का संदेह है, और वह यथोचित रूप से मानता है कि सीडीडी प्रक्रिया करने से ग्राहक सतर्क हो जाएगा, तो वे सीडीडी प्रक्रिया का पालन नहीं करें, और इसके बजाय एसटीआर फाइल करें।

IX. नई तकनीकों का परिचय

यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरई नए उत्पादों के विकास और नई व्यावसायिक प्रथाओं, जिसमें नए वितरण तंत्र, और नए तथा पहले से मौजूद दोनों उत्पादों के लिए नई या विकासशील तकनीकों का उपयोग शामिल है, के संबंध में उत्पन्न होने वाले एमएल/टीएफ जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन कर सकते हैं, अनुदेशों में संशोधन किया गया है, । तदनुसार, आरई ऐसे उत्पादों, प्रथाओं, सेवाओं और प्रौद्योगिकियों को लाने या उपयोग से पहले जोखिम मूल्यांकन करेंगे; और जोखिमों को प्रबंधित करने और कम करने के लिए उचित उपाय करेंगे।

X. व्यापक समुचित सावधानी (अप्रत्यक्ष ग्राहक ऑनबोर्डिंग)

धारा 40 में कुछ अतिरिक्त संवर्धित समुचित सावधानी उपायों को जोड़ा गया है। खाते में परिचालन की अनुमति देने से पहले आरई सकारात्मक पुष्टि के माध्यम से वर्तमान पते को सत्यापित करेंगे, ग्राहक से पैन प्राप्त किया जाएगा और सत्यापित किया जाएगा, ग्राहकों को उच्च जोखिम वाले ग्राहकों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और अप्रत्यक्ष प्रारूप में खोले गए खातों पर तब तक निगरानी बढ़ाई जाएगी जब तक कि ग्राहक की पहचान प्रत्यक्ष या वी-सीआईपी आदि के माध्यम से सत्यापित नहीं हो जाती।

XI अन्य अनुदेशों में संशोधन

क) परिभाषाएँ

"समूह" की परिभाषा जोड़ी गई है। इसके अलावा, "गैर- लाभकारी संगठनों" और "राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण व्यक्तियों" की परिभाषाओं को पीएमएल नियमों में परिभाषाओं के साथ संरेखित करने के लिए संशोधित किया गया है।

ख) सामान्य

(i) धारा 4 में संशोधन किया गया है और आरई को सूचना देते हुए एक प्रावधान जोड़ा गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) के अध्याय IV के प्रावधानों के तहत दायित्वों के निर्वहन के उद्देश्य से एक समूह-व्यापी नीति लागू की गई है।

(ii) एफआईयू-आईएनडी को सूचित करने के अलावा, आरई नामित निदेशक और प्रधान अधिकारी का नाम, पदनाम, पता और संपर्क विवरण रिज़र्व बैंक को सूचित करेंगे।

ग) ग्राहक स्वीकृति नीति

अनुदेशों में संशोधन यह स्पष्ट करने के लिए किया गया है कि अतिरिक्त जानकारी, जहां आरई की आंतरिक केवाईसी नीति में ऐसी जानकारी की आवश्यकता निर्दिष्ट नहीं की गई है, ग्राहक की स्पष्ट सहमति से प्राप्त की जाती है।

जहां जीएसटी नंबर उपलब्ध है, इसे जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा प्रदान की गई खोज/सत्यापन सुविधा के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा।

घ) जोखिम वर्गीकरण

धारा 12 में यह प्रावधान शामिल करने के लिए संशोधन किया गया है कि, "ग्राहकों के जोखिम-वर्गीकरण के लिए आरई द्वारा व्यापक सिद्धांत निर्धारित किए जा सकते हैं"। भौगोलिक जोखिम को कवर कर ग्राहकों के साथ-साथ लेन-देन, उत्पादों/सेवाओं के प्रकार, उत्पादों/सेवाओं के वितरण के लिए उपयोग किए जाने वाले वितरण चैनल, किए गए लेनदेन के प्रकार आदि को शामिल करने के लिए जोखिम वर्गीकरण के लिए मापदंडों की सांकेतिक सूची का विस्तार किया गया है।आरई जोखिम वर्गीकरण और ग्राहकों के जोखिम वर्गीकरण के कारणों को गोपनीय मानेंगे।

ड.) व्यक्तियों के लिए ग्राहक समुचित सावधानी (सीडीडी)

धारा 16 को विशेष रूप से यह स्पष्ट करने के लिए संशोधित किया गया है कि आरई सीडीडी के उद्देश्य से सीकेवाईसीआर से केवाईसी रिकॉर्ड डाउनलोड करने के लिए स्पष्ट ग्राहक सहमति के साथ केवाईसी आइडेंटीफायर प्राप्त कर सकते हैं।

च) आधार ओटीपी आधारित ई-केवाईसी का उपयोग करते हुए, अप्रत्यक्ष रूप में खाता खोलना

इस तरह के खातों के लिए निम्नलिखित जोखिम कम करने के उपायों को प्रक्रिया में जोड़ा गया है—

"आरई यह सुनिश्चित करेंगे कि लेन-देन अलर्ट, ओटीपी आदि केवल ग्राहक के आधार के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे जाएं। आरई के पास ऐसे खातों में मोबाइल नंबर बदलने के अनुरोधों को देखने के लिए समुचित सावधानी की सुदृढ़ प्रक्रिया को दर्शाने वाली बोर्ड अनुमोदित एक नीति हो।"

छ) वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया (वी-सीआईपी)

वी-सीआईपी इंफ्रास्ट्रक्चर और वी-सीआईपी में व्यवधान से संबंधित कुछ अनुदेशों में संशोधन किया गया है। इसके अलावा, - (i) आधार एक्सएमएल फाइल/आधार सुरक्षित क्यूआर कोड की वैधता और (ii) वीडियो प्रक्रिया शुरू करने के लिए 'तीन दिनों' की आवश्यकता को 'तीन कार्य दिवस' कर संशोधित किया गया है।

ज) एकल स्वामित्व फर्मों के लिए सीडीडी उपाय

धारा 28 को यह स्पष्ट करने के लिए संशोधित किया गया है कि मालिकाना फर्म के नाम पर व्यवसाय/गतिविधि के प्रमाण के रूप में "पंजीकरण प्रमाणपत्र" में "सरकार द्वारा जारी उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र (यूआरसी)" शामिल है।

झ) जारी समुचित सावधानी

जारी समुचित सावधानी के लिए, आरई प्रभावी निगरानी का समर्थन करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग (एआई और एमएल) सहित उपयुक्त नवाचारों को अपनाने पर विचार कर सकते हैं।

ट) अंतरराष्ट्रीय करारों के तहत आवश्यकताएँ / दायित्व - अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से संचार

नवीनतम तकनीकी नवाचारों और उपकरणों का लाभ उठाने के लिए आरई की आवश्यकता वाली एक नई धारा 54ए शुरू की गई है ताकि प्रतिबंधों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नाम स्क्रीनिंग का प्रभावी कार्यान्वयन किया जा सके ।

ठ) गोपनीयता दायित्व

यह स्पष्ट किया गया है कि गोपनीयता दायित्व सभी आरई पर लागू होंगे

ड) सीकेवाईसीआर पर अनुदेश

अनुदेशों में संशोधन यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि सीकेवाईसीआर से डाउनलोड किए गए केवाईसी दस्तावेज, , लेकिन जिनकी वैधता समाप्त हो गई है, को डाउनलोड करने वाली आरई द्वारा केवाईसी उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाता है।

ढ) विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड (यूसीआईसी)

ग्राहकों को यूसीआईसी आवंटित करने की आवश्यकता को सभी आरई तक बढ़ा दिया गया है।

ण) कर्मचारियों की भर्ती और प्रशिक्षण

केवाईसी/एएमएल/सीएफटी मामलों से निपटने वाले आरई के कर्मचारियों के बीच खुले संचार, उच्च सत्यनिष्ठा, विषय वस्तु की उचित समझ के तत्वों को शामिल करने के लिए अनुदेशों में संशोधन किया गया है।

त) धारा 72 का विलोपन

"एनबीएफसी/आरएनबीसी और ब्रोकर/एजेंट आदि सहित एनबीएफसी/आरएनबीसी द्वारा अधिकृत व्यक्तियों द्वारा अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) दिशानिर्देशों का पालन करने" से संबंधित धारा 72 को हटा दिया गया है।

थ) यूएपीए केंद्रीय (नामित) नोडल अधिकारी में परिवर्तन

प्रभार के अंतरण के परिणामस्वरूप, यूएपीए के लिए केंद्रीय [नामित] नोडल अधिकारी संयुक्त सचिव के स्थान पर अतिरिक्त सचिव (सीटीसीआर), गृह मंत्रालय हैं। यूएपीए आदेश के पैरा 3.1 (केवाईसी पर एमडी के अनुबंध II) को तदनुसार संशोधित किया गया है।